

इच्छा के खिलाफ निकाह

(तेरहवें फ़िक्रही सेमिनार में पास किया गया प्रस्ताव)

1- बालिग होने के बाद हर लड़का या लड़की को शरीअत ने अपने मामले में अपनी इच्छा के अनुसार फैसला करने का अधिकार दिया है। निकाह के लिए भी यह अधिकार समान रूप से हासिल है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता इस्लाम की एक अहम विशेषता है। पश्चिमी और पूर्वी देशों में बसने वाली बहुत सी क्रौमों ने इस्लाम की इन शिक्षाओं से प्रभावित होकर ही अपने यहाँ औरतों को बहुत से अधिकार दिए हैं।

2- किसी वली की तरफ से लड़के या लड़की को उसकी इच्छा के खिलाफ किसी रिश्ते पर मजबूर करना जायज़ नहीं है। इस संबंध में किसी तरह का दबाव बनाना या धमकी देना इस्लाम के द्वारा दिए गये व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन है।

3- लड़के और लड़की को यह प्रेरणा दी जाती है कि वह अपने वली की इजाजत और मशवरे से ही निकाह करें, और उनकी तरफ से चुने गए रिश्ते को प्राथमिकता दें। क्यूंकि उनकी मुहब्बत और उनका जीवन अनुभव उन्हें आगे के नुकसान और पछतावे से बचाएगा। यह आशा रखनी चाहिए कि वली या अभिभावक रिश्ते के चयन में उनके हित और भविष्य का पूरा ख्याल रखेंगे।

4- निकाह सम्पन्न होने या न होने का सम्बन्ध निकाह के समय रजामंदी के इजहार से है, इस लिए अगर बालिग लड़के या लड़की ने निकाह के समय रजामंदी दे दी तो निकाह सम्पन्न हो जाएगा।

5- अगर क़ाज़ी या शरई अदालत के सामने यह बात साबित हो जाए कि अभिभावकों ने बालिग लड़की के निकाह के सिलसिले में ज़ोर ज़बरदस्ती से काम लिया है और उसकी इच्छा के खिलाफ जबरन निकाह कराया है, और लड़की इस निकाह को बाक़ी नहीं रखना चाहती तो क़ाज़ी या शरई संस्था को यह निकाह खत्म (फ़स्ख) कराने का अधिकार हासिल हो जाएगा।

☆☆☆